सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र

माननीय अदालत डी. एस. तेवतिया, जे.

दलीप सिंह,-अपीलार्थी

बनाम

धर्मन और अन्य,-प्रत्यर्थी

1966 की दूसरी अपील संख्या 1206 '

सितम्बर 16,1970

हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम (1956 का LXXVIJI)-धारा 13-क्या 'दत्तक पिता को अलगाव का अधिकार प्रदान करता है जहां उसे नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत कोई भी मौजूद नहीं है।

अभिनिर्धारित है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 13. संपत्ति के प्रत्यावर्तन का अधिकार प्रदान नहीं करती है जहां यह सामान्य विधि के अधीन विद्यमान नहीं है और उस मामले के लिए यह देखना होगा कि या तो पक्ष हिंदू विधि या प्रथागत विधि द्वारा शासित हैं। जहां एक दत्तक पिता प्रथागत कानून द्वारा शासित होता है जो पैतृक संपत्ति के अलगाव को प्रतिबंधित करता है, अधिनियम की धारा 13 उसे ऐसी संपत्ति को अलग करने का अधिकार नहीं देती है। (Paragraph 3)

श्री के. एस. सिद्धू, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत के डिक्री से नियमित दूसरी अपील, दिनांक 25 जून, 1966, जिसमें श्री शिव दास त्यागी, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, झज्जर की पुष्टि की गई थी, दिनांक 13 सितंबर, 1965, वादी के वाद को खारिज करते हुए। दोनों न्यायालयों ने पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया।

एस. पी. जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए के. एल. साचेडेवा, अधिवक्ता।

फैसला

1) यह अपील वादी-अपीलार्थी के आग्रह पर इस आशय की घोषणा के लिए एक वाद से उत्पन्न होती है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में दिया गया उपहार वादी पर बाध्यकारी नहीं होगा और यह कि इसका प्रतिवादी संख्या 1, धर्म के दत्तक पुत्र के रूप में उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी-अपीलार्थी द्वारा अपने वाद में यह आरोप लगाया गया है कि उसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्तमान वाद की स्थापना से लगभग चार साल पहले गोद लिया गया था और तब से वह अपने दत्तक पुत्र के रूप में उसके साथ रह रहा था। यह आगे आरोप लगाया गया है कि पक्ष जाट हैं और प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं और भूमि का पैतृक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कानूनी रूप से अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए विचाराधीन अलगाव अवैध है और प्रत्यावर्तकों के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। अभियुक्तों ने मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 2 और 3, प्रतिवादी संख्या 1 की बेटियों के पक्ष में भूमि का उपहार स्वीकार किया गया था, लेकिन यह तथ्य कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का गोद लिया हुआ पुत्र था या विवाद में संपत्ति पैतृक थी, विवादित था। पक्षकारों की दलीलों के कारण निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया गया –

" (1) क्या वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गोद लिया गया था और क्या वह उसका गोद लिया हुआ पुत्र है?
(2) यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो क्या विवादित संपत्ति पैतृक है जो वादी है?
(3) क्या पक्षकार अलगाव और उत्तराधिकार के मामलों में प्रथा द्वारा शासित होते हैं। यदि हां, तो उक्त प्रथा क्या है?
(4) क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में दिया गया उपहार शून्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है?
(5) क्या वाद निर्धारित है। यदि ऐसा है तो इसका क्या असर होगा?
(6) क्या वादी के पास मुकदमा दायर करने का अधिकार है?
(7) राहत।"

विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकार प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, कि भूमि गैर-पैतृक थी और वादी को उसके आरोप के अनुसार गोद लिया गया था। इसने आगे कहा कि चूंकि वादी का गोद लेने के समय पहले से ही एक बेटा था, इसलिए उसे रोहतक जिले के रिवाज-ए-आम के अनुसार वैध रूप से गोद नहीं लिया जा सकता था। हालाँकि, मुकदमे को निचली अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संपत्ति गैर-पैतृक होने के कारण अलग-थलग की जा सकती है और इसलिए उक्त संपत्ति का उपहार वादी पर वैध और बाध्यकारी था। वादी के कहने पर एक अपील निचली अपीलीय अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिए वादी के कहने पर यह दूसरी अपील है।

2) यहां यह कहा जा सकता है कि निचली अपीलीय अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विचाराधीन दत्तक ग्रहण 1956 के हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के प्रारंभ के बाद किया गया था, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है, इसलिए यह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित माना जाएगा, जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि दत्तक पिता या माता उपहार या वसीयत द्वारा उनके द्वारा धारण की गई संपत्ति को अलग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
3) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि भले ही अधिनियम मामले को नियंत्रित करने के लिए आयोजित किया जाता है, धारा 13 के प्रावधान अलगाव का अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं जहां यह सामान्य कानून के तहत मौजूद नहीं है और चूंकि पक्ष प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं, जो पैतृक संपत्ति के अलगाव को प्रतिबंधित करता है, इसलिए उक्त अलगाव की वैधता प्रथागत कानून के प्रावधानों के संदर्भ में तय की जानी चाहिए। इस तर्क में योग्यता है कि अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान संपत्ति के अलगाव का अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं जहां यह सामान्य कानून के तहत मौजूद नहीं है और उस मामले के लिए यह देखना होगा कि क्या पक्षकार, अलगाव के उद्देश्य से, हिंदू कानून या प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं। वर्तमान मामले में नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार प्रथागत विधि द्वारा शासित हैं और इसलिए विचाराधीन अलगाव की वैधता प्रथागत विधि के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। इस मामले में प्रथागत विधि के प्रावधान भी अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि विचारण न्यायालय ने संपत्ति को गैर-पैतृक पाया है और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को निचली अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी के विद्वत वकील ने आग्रह किया है कि चूंकि निचली अपीलीय अदालत ने विचार किया कि अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुप्रयोग ने मामले को समाप्त कर दिया है, इसलिए उसने मामले के दूसरे पहलू पर अपना विचार लागू नहीं किया। इसलिए यह अवलोकन कि संपत्ति की गैर-पैतृक प्रकृति के बारे में निष्कर्ष पर सवाल नहीं उठाया गया है, इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि संपत्ति की गैर-पैतृक प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निचली अपीलीय अदालत के समक्ष वकील द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने वैकल्पिक रूप से आग्रह किया है कि भले ही इस तरह की रियायत वकील द्वारा दी गई हो, लेकिन कानून के प्रश्न के संबंध में ऐसी कोई रियायत बाध्यकारी नहीं हो सकती है। यह निर्णय किए बिना कि क्या

विचाराधीन रियायत वादी-अपीलार्थी पर बाध्यकारी थी या नहीं, मैंने विद्वान वकील को यह दिखाने की अनुमति दी कि संपत्ति की गैर-पैतृक प्रकृति के संबंध में निचली अदालत का निष्कर्ष कैसे गलत है। विद्वान वकील ने संपत्ति की गैर-पैतृक प्रकृति के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की शुद्धता को इस आधार पर चुनौती दी कि विचाराधीन संपत्ति धर्मन को एक अधिभोग किरायेदार के रूप में अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, हालांकि स्वामित्व अधिकार उनके द्वारा पहली बार अर्जित किए गए थे। यहां यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक अधिभोग किरायेदार अपने स्वामित्व वाली भूमि में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करता है, तो विचाराधीन संपत्ति को उसकी स्व-अर्जित संपत्ति माना जाता है। इस संबंध में, सावन सिंह और अन्य बनाम अमर नाथ (1963 P.L.R. 82) और संगत सिंह बनाम इशर सिंह और अन्य(A.I.R. 1927 Lah. 536(1)) देखें। चूंकि विवादित भूमि को गैर-पैतृक माना जाता है, इसलिए ऐसी संपत्ति के अलगाव को प्रभावित करने के लिए प्रथागत कानून के तहत भी कोई रोक नहीं है।

4) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा